

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक 4(21) ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/2009-10

जयपुर, दिनांक:-

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

18 JUN 2010

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत एमआईएस के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्र सरकार द्वारा पत्रांक संख्या जे-11060/8/2010-नरेगा दिनांक 31.05.2010 (प्रति संलग्न) द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि योजनान्तर्गत राशि का आवंटन एमआईएस के आधार पर ही किया जायेगा। केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी केन्द्रीय अंश की राशि का आवंटन एमआईएस के आधार पर ही किया जा सकेगा। योजनान्तर्गत राशि की मांग केन्द्र सरकार की अधिकृत वेबसाइट nrega.nic.in पर ऑनलाइन ही की जानी है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वर्ष 2010-11 की प्रगति एमआईएस पर तुरन्त ही अपलोड की जावे।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2010-11 का समस्त बैकलॉग मुख्य रूप से मस्टररोल, सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद पर व्यय की प्रविष्टि 15 जुलाई, 2010 तक पूर्ण कर ली जावे तथा उसके उपरान्त इस प्रकार की व्यवस्था की जावे कि एमआईएस पर बैकलॉग होने ही नहीं पाये। इसके लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत एमआईएस मैनेजर के साथ साप्ताहिक मीटिंग एवं बैकलॉग समाप्त हो जाने पर पाक्षिक मीटिंग द्वारा एमआईएस प्रगति की समीक्षा की जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रगति समय पर एमआईएस पर अपलोड हो जाये। राज्य स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जायेगी। वर्तमान में यदि वर्ष 2009-10 का डाटा अपलोड होने से शेष है तो उसे आउटसोर्स के माध्यम से पूर्ण कराया जावे एवं वर्ष 2010-11 का डाटा जिलों में उपलब्ध डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ऑपरेटर मय मशीन के माध्यम से पूर्ण कराया जावे। जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ऑपरेटर मय मशीन नियोजित किये जाने के निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। इनका नियोजन प्राथमिकता से किया जाकर इनकी सेवाएं डाटा अपलोड के उपयोग में ली जावे।

भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध सचेत (Alerts) में बेरोजगारी भत्ते की स्थिति, विलम्बित भुगतान, श्रमिकों की खाता संख्या की प्रविष्टि एवं फोटो अपलोडिंग इत्यादि सचेत की नियमित समीक्षा की जाये एवं इनको हटाने की आवश्यक कार्यवाही तुरन्त सम्पादित की जावे।

भारत सरकार द्वारा इस संबन्ध में दिये गये संलग्न निर्देशों का आप व्यक्तिगत रूप से स्वयं भी अवलोकन करें एवं दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे ताकि योजनान्तर्गत राशि के आवंटन में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

13/06/10
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि: अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (प्रथम)

As you are aware, the first tranche is released equivalent to the requirement of first six months subject to 50% of the fund requirement for the whole year based on the agreed to LB after adjusting funds available as opening balance on the 1st day of the financial year.

In order to enable Ministry to release 1st tranche immediately after the Labour Budget is agreed to, the States should also ensure fulfilment of following conditionalities:-

- (a) District-wise opening balance figures as on April 1 of the financial year for which 1st tranche would be released.
- (b) District-wise and month-wise projections of the labour demand and the fund requirement as per agreed to Labour Budgets.
- (c) Accounts of the financial year before last should have been settled.
- (d) Settlement of audit paras.
- (e) Satisfactory reply of all clarifications sought by the Ministry.

2. The software being developed for submission of online proposals by the States/Districts for the release of 2nd tranche would be shared with States very soon. Accordingly, the Ministry would only accept online proposals for release of 2nd tranche henceforth. The details of which has already been shared and discussed with States in the above Workshop which are also detailed below:-

Pre-requisite for release of 2nd Tranche - 2010-11

The software has been programmed to accept online financial proposals only if the following conditionalities are met:

- (a) Updated physical progress in terms of employment demand generated (persondays) and financial progress have been reported.
- (b) Full State share proportionate to Central release till then is released and received by districts. In case of State having State Fund, it should be released and made available in the Mahatma Gandhi NREGA Savings Bank Account duly certified by the concerned Bank.
- (c) Expenditure incurred reaches 60% of available funds.
- (d) 100% reporting is made on MIS.
- (e) Provision for Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra.
- (f) UC of previous year and current year would be generated through MIS, pending audit paras should have been answered and other prescribed certificates as per the guidelines like non-diversion, non-embezzlement, etc. must accompany the proposal.
- (g) Proposal to be accompanied with complete audit report if the same is submitted on 1st October and thereafter.
- (h) Consistency in Opening Balance and Closing Balance as per audit report, UC and MPR of the last year.
- (i) Complaints/VIP references to be resolved under the given time frame.
- (j) Conduct of regular Social Audit. Findings of Social Audit to be uploaded and action taken on findings within 3 months to be on MIS.
- (k) Ombudsman to be instituted before coming up for 2nd Tranche.
- (l) If wages higher than notified wage are paid then the amount by which it is higher should be from State Share with proportionate material component that should have been released if material component exceeds proportionate 40% of the notified wages.

Contd..3/...

3. I would like to thank you for your positive and affirmative response on the above proposed improvements in the procedural aspects and with your cooperation, I am sure that overall efficacy in the implementation of the Mahatma Gandhi NREGA could be further enhanced. This will also bring in greater element of financial prudence in overall implementation of the Act.

o/c

Principal Secretaries/Secretaries
of all the States(in-charge of NREGA)

Yours sincerely,

(BK Sinha)

1-6-10